उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

9 मई, 2018 • वर्ष 1, अंक 16

सात दिन – सात पृष्ठ

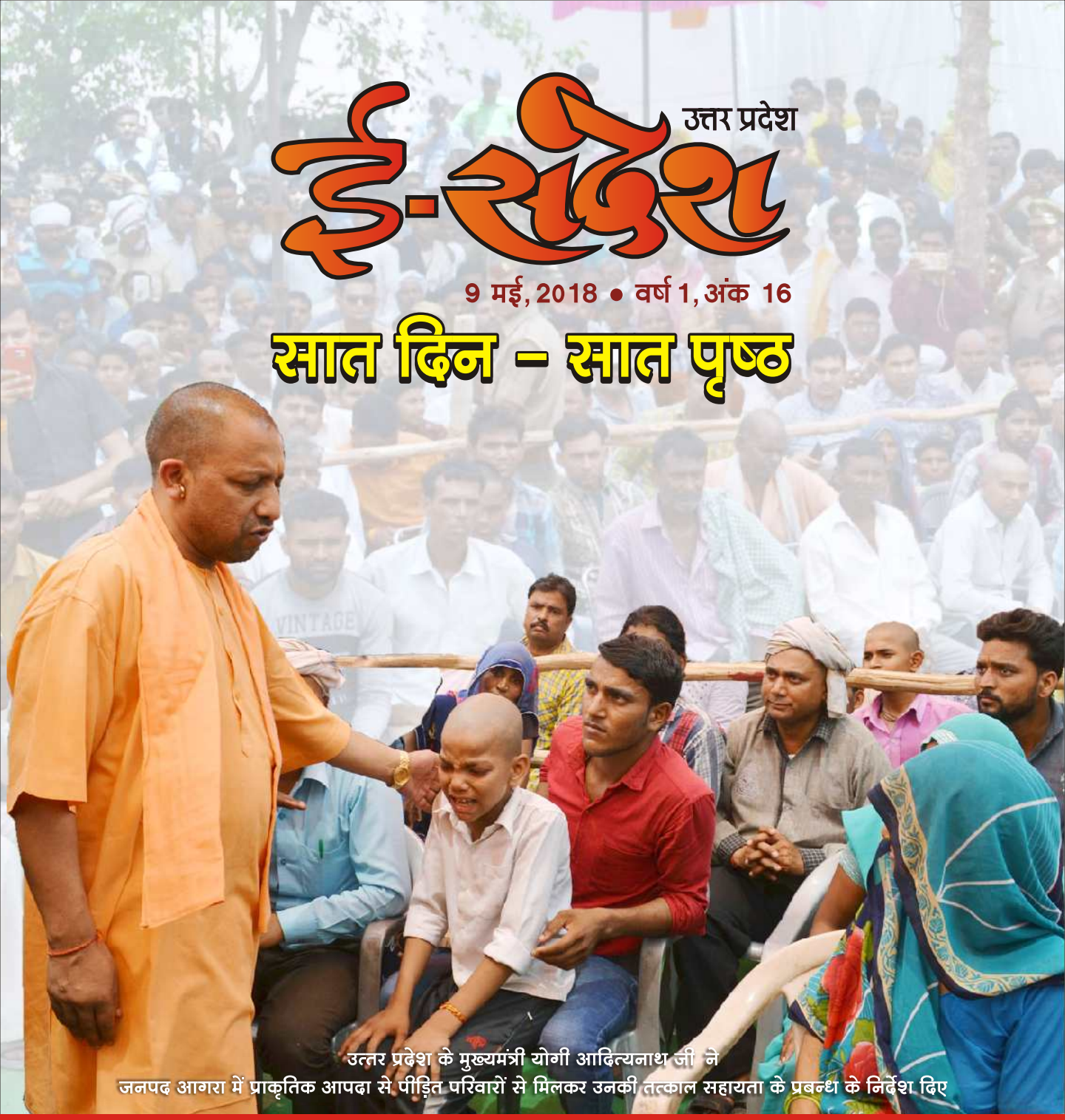

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
जनपद आगरा में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी तत्काल सहायता के प्रबन्ध के निर्देश दिए

- आपदा प्रभावित गांवों में राजस्व व बिजली बिल वसूली स्थगित
- पीएचडी चैम्बर्स के यूपी चैप्टर की शुरूआत
- प्रदेश में अब तक 25.33 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद
- टीईटी शिक्षामित्रों को नहीं होगी कोई समस्या
- देश में निवेश हेतु सबसे सुरक्षित स्थल है उत्तर प्रदेश
- लखनऊ में बनेगा देश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेटर

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री जी ने बांटा आपदा प्रभावित परिवारों का दु:ख–दर्द

आगरा तथा अन्य आपदा प्रभावित स्थानों, जहां सड़कों पर बड़े–बड़े पेड़ गिर गये हैं, उन्हें तत्काल हटवाया गया। जिन क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, वहां पर टैंकर आदि से पेयजल की व्यवस्था की गई।

ऐसे परिवार जिनके आवास पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं और रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके रहने की व्यवस्था की गई है। उन्हें खाद्यान्न सामग्री व तेल आदि उपलब्ध कराए जाए। मौसम विभाग की एडवाइजरी के अनुसार लोगों व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की गई। प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध करायी जा रही है। अस्पताल में आपदा से घायल लोगों को नि:शुल्क उपचार, साफ–सफाई तथा भोजन की बेहतर से बेहतर व्यवस्था भी कराई गई है।

आपदा प्रभावित गांवों में राजस्व व बिजली बिल वसूली स्थगित

प्रदेश के आपदा प्रभावित तहसीलों में राजस्व व विद्युत देयों की वसूली स्थगित करा दी गई है, ताकि जनता को कोई समस्या न हो। आपदा प्रभावित क्षेत्र के निराश्रित विवाह योग्य कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कराया जायेगा। दिव्यांगजन को आवश्यक उपकरण तथा पात्रों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा।

पीड़ितों को समय से मिलगा मुआवजा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लोगों को समय से मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। फसल व बागवानी को हुई क्षति का आकलन कराकर प्रभावित लोगों को सहायता दी जा रही है। तिलहन व दलहन के क्रय केन्द्रों की व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आम जन के दु:ख–दर्द में सदैव उनकी सहायता करने हेतु तत्पर रहते हैं। उनका यही दर्दमंद रूप उस समय दृष्टिगोचर हुआ जब वह प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने न केवल पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढ़ाढस बंधाया और उनकी आर्थिक मदद की बल्कि उनकी हर संभव सहायता का वादा भी किया।

भावुक हुए मुख्यमंत्री जी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद आगरा में आंधी–तूफान की आपदा में घायल लोगों से मुलाकात की। ग्राम बाद निवासी एक ही परिवार के तीन बच्चों आसू, दिव्यांश और दिव्यांशी को देखकर मुख्यमंत्री जी भावुक हो गये। जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के पश्चात् मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रभावित लोगों व मृतक के परिजनों को राहत धनराशि के चेक वितरित किए। उन्होंने सदर तहसील के ग्राम धांधूपुर में विद्युत तार गिरने से मृतक के परिजनों को भी सांत्वना दी।

राहत और पुनर्वास का प्रबंध

मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास हेतु अधिकारियों को व्यापक निर्देश दिए। आपदा से सर्वाधिक प्रभावित गांवों व पीड़ित परिवारों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से विशेष अभियान चलाकर लाभान्वित किया जाएगा। आपदा से प्रभावित ऐसे लोग, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं तथा जिन्हें अन्य आवासीय योजनाओं से भी आवास नहीं मिला है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा।

> **प्रदेश सरकार दैवीय आपदा से पीड़ित परिवारों के दुख दर्द में साथ खड़ी है**
> **–मुख्यमंत्री**

पीड़ितों के साथ है सरकार

सरकार पीड़ितों के साथ है तथा उन्हें हर सम्भव मदद दिलायी जायेगी। किसी भी पीड़ित को मुआवजा पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। चक्रवाती तूफान के बाद पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के भीतर राहत उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत 98 प्रतिशत पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराई जा चुकी है और शेष को उपलब्ध कराने की कार्यवाही तेजी से चल रही है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रामदास अठावले ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने श्री अठावले को डॉ0 भीमराव आंबेडकर के नाम परिवर्तन की पुस्तिका भी भेंट की।

पीएचडी चैम्बर्स के यूपी चैप्टर की शुरूआत

उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े प्रदेश के रूप में जाना जाता है। मानव संसाधन की दृष्टि से यहाँ के मानव संसाधन का सही उपयोग किया जाये तो उत्तर प्रदेश 'उत्तम प्रदेश' ही नहीं भारत का 'सर्वोत्तम प्रदेश' बन सकता है।

राज्यपाल श्री राम नाईक ने यह विचार पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के उत्तर प्रदेश स्टेट चैप्टर के उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि देश के विकास में उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व है। पीएचडी चैम्बर ने प्रदेश के विकास का जो संकल्प लिया है उससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास में कैसे आगे बढ़े, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के लोगों को भी संस्था से प्रेरणा लेकर प्रदेश के विकास में आगे आना चाहिए। किसी भी देश एवं प्रदेश के विकास में वहाँ के मानव संसाधन का विशेष योगदान होता है। देश के मानव संसाधन का उचित मार्गदर्शन होना चाहिए नहीं तो वह गलत रास्ते पर चले जायेंगे। प्रदेश में पर्याप्त भूमि, सिंचाई के साधन तथा अनुकूल वातावरण है जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक ताकत है।

इंवेस्टर्स समिट के आयोजन से प्रदेश में निवेशकों के लिए अच्छा माहौल बना है। प्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सुदृढ़ कानून एवं व्यवस्था, पर्याप्त बिजली की उपलब्धता के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।

प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता एवं प्रमाणिकता के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म किया जा रहा है। इसका लाभ सभी प्रदेशवासियों को मिलेगा तथा उत्तर प्रदेश 'सर्वोत्तम प्रदेश' बनने में सफल होगा।

राज्यपाल ने अपनी पुस्तक 'चरैवेति! चरैवेति!!' का मर्म समझाते हुये कहा कि जो लगातार चलता रहता है उसका भाग्य भी लगातार चलता रहता है। इसलिए प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ■

देश में निवेश हेतु सबसे सुरक्षित स्थल है उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश बना नंबर वन

- प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेण्ट योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष में स्किल डेवलपमेण्ट सहित अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से 04 लाख युवाओं का प्रशिक्षण कराकर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 02 लाख 60 हजार युवाओं का प्लेसमेण्ट कराया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8.85 लाख आवास की स्वीकृति देने के साथ उत्तर प्रदेश 17वें स्थान से प्रथम स्थान पर पहुंच गया है।
- स्वच्छता मिशन के अंतर्गत बड़ी संख्या में शौचालय निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश 23वें स्थान से प्रथम स्थान पर आ गया है।
- 43 लाख परिवारों को नि:शुल्क विद्युत संयोजन उलब्ध कराकर प्रदेश विद्युतीकरण में भी प्रथम स्थान पर है।

वर्तमान सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है। एक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कानून–व्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों से प्रदेश में व्यापक निवेश का वातावरण बना है।

एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास के रोडमैप को देश और प्रदेश के सामने रखा है। इस समिट में हस्ताक्षरित 4 लाख 68 हजार करोड़ रुपए के एमओयू में से लगभग एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को तीन माह की अल्प अवधि में ही अमलीजामा पहनाने के करीब पहुंचाया गया है। सभी एमओयू के धरातल पर उतरने पर लगभग 33 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।

बढ़ी रीजनल कनेक्टिविटी

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब उद्यमियों के लिए यह राज्य निवेश हेतु सर्वाधिक सुरक्षित स्थल बन गया है। प्रदेश में इस बदलाव के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक फैसले लेकर जमीनी स्तर पर काम किया गया है। प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है। पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी हवाई अड्डे ही संचालित थे, जबकि वर्तमान में आगरा और गोरखपुर हवाई अड्डा भी संचालित है।

नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नंबर वन यूपी

योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नम्बरवन हो गया है। वर्तमान सरकार की नीति व उड़ान योजना के माध्यम से शीघ्र ही हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर लगभग 20 हो जाएगी। लखनऊ हवाई अड्डे पर बन रहे नये टर्मिनल में लखनऊ की संस्कृति की खूबियां प्रदर्शित की जाएंगी। जेवर में लगभग 05 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास एअरपोर्ट के निर्माण से प्रदेश के विकास को जो गति मिलेगी, वह कल्पना से परे है। बन जाने के पश्चात ऐसा एयरपोर्ट पूरे देश में कहीं नहीं होगा।

एक्सप्रेस–वे से जुड़ेगा पूर्वांचल

वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के पूर्वान्चल क्षेत्र को एक्सप्रेस–वे से जोड़ा जा रहा है। बुन्देलखण्ड के लिए भी एक्सप्रेस–वे की योजना है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के अतिरिक्त रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा राज्य के लिए घोषित 03 रेल कारखानों की स्थापना के लिए तत्परता से कार्य हो रहा है।

प्रदेश में अब तक 25.33 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद

रबी खरीद वर्ष 2018-19 के तहत प्रदेश में खोले गए गेहूँ क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक 25,33,079 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हो चुकी है। इसके एवज में 4,45,898 किसानों के खातों में 4363.91 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। गत वर्ष इस समयावधि में 12,90,066.16 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गयी थी।

गत वर्ष की तुलना में इस साल दोगुने से अधिक खरीद हुई है। खरीद लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 50 प्रतिशत से अधिक खरीद की जा चुकी है।

अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु सरकार की ठोस पहल

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अनुपजाऊ/बीहड़ पड़ी जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिए ठोस पहल शुरु की है। सरकार का प्रयास है कि किसी भी जिले में अनुपजाऊ भूमि न रहे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को प्रभावी रणनीति बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऊसर और बीहड़ क्षेत्रों को उपचारित करके उन्हें फसलोत्पादन के योग्य बना कर किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी, वहां रोजगार के अवसर सृजित होगें।

गत वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 11 बीहड़ जनपदों कानपुर देहात, फतेहपुर, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, बाराबंकी, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर और सुल्तानपुर में भूमि सुधार का कार्यक्रम चलाया गया। इन जनपदों में 19199 हेक्टेयर बीहड़ क्षेत्रफल को उपचारित करके 30 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया, जिस पर किसानों ने विभिन्न फसलें पैदाकर लाभ अर्जित किया है।

1364650 मानव रोजगार दिवस सृजित हुए ऊसर सुधार योजना से

33 करोड़ रुपये से उपचारित की गई 11 जिलों में 19199 हैक्टेयर भूमि

11 जिलों के बीहड़ क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने पर लगभग 33 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इससे 1364650 मानव दिवसों का रोजगार सृजित कर किसानों और श्रमिकों को लाभ मिला है। सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र यमुना नदी के जलमटे क्षेत्र में स्थित सहायक नदियां चम्बल, काली, क्वारी, केन, सेंगर आदि के दोनों ओर स्थित जनपदों में है। योजना से फसल पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। गेंहू, दलहन, चारा एवं शाकभाजी के क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई। भूमि के मूल्य में डेढ़ से तीन गुना तक वृद्धि हुई।

बीहड़ सुधार परियोजना राज्य की बीहड़ भूमि को सुधारने/उपचारित करने तथा कृषि एवं पशुधन उत्पादकता की वृद्धि में काफी सहायक सिद्ध हुई है। इसमें न केवल भूमि का कटाव रुका, बल्कि क्षेत्र का विकास भी सुनिश्चित हुआ। ■

वन ड्राप, मोर क्राप योजना से किसानों को लाभ

बुंदेलखण्ड की चार नहरों को जल उपभोक्ता समितियों को सौंपने के कार्य की विश्व बैंक ने की सराहना

नहरों का पूर्ण प्रबंध निर्वाचित जल उपभोक्ता समितियों को सौपना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार ने हर खेत तक समय से पानी पहुंचाकर प्रसंशनीय कार्य किया हैं। प्रदेश सरकार वन ड्राप, मोर क्राप योजना का लाभ किसानों तक पहुचाने के लिए सतत् प्रयास कर रही है जिससे कि कम पानी में किसान अधिक पैदावार प्राप्त कर सके।

किसानों की समस्याओं के निराकरण पर जोर

परियोजना के लाइन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों की समास्याओं के निवारण के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र का भ्रमण करें तथा आ रही समस्याओं का निराकरण मौके पर ही करें।

बुंदेलखण्ड़ के बेतवा संगठन की चार नहरों (छपरौनी, गढौली, चौका एवं तिसगना) का सम्पूर्ण प्रबंध निर्वाचित जल उपभोक्ता समितियों को विश्व बैंक टीम की उपस्थिति में सौप दिया गया। विश्व बैंक टीम ने इस अभिनव कार्य की सराहना की है।

बुंदेलखण्ड़ की 711 जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराकर उनका कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्य भी पूरा हो चुका हैं। शीघ्र ही शेष समितियों को भी नहरों का प्रबंध भी सौप दिया जायेगा।

टीईटी शिक्षामित्रों को नहीं होगी कोई समस्या

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने टी.ई.टी. पास शिक्षामित्रों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट कर बेसिक शिक्षा परिषद में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में टी.ई.टी. पास शिक्षामित्रों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में यथोचित प्राथमिकता दिए जाने और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पास अंकों की सीमा में छूट तथा 25 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक तथा टी.ई.टी.–2013 की वैधता को भर्ती परीक्षा में अनुमन्य किए जाने का भी अनुरोध किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमण्डल की मांगों को स्वीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए, ताकि भर्ती परीक्षा में टी.ई.टी. पास शिक्षामित्रों को किसी प्रकार की समस्या न आए।

महिलाओं के सशक्तीकरण से बदली प्रदेश की तस्वीर

स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर मिली महिलाओं को आर्थिक आजादी, जीवन में आया परिवर्तन

ग्रामीण अंचलों में रहने वाली गरीब वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बना कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जहां एक ओर सुदृढ़ किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की बढ़–चढ़ कर भागीदारी से स्पष्ट है कि अब गांवों में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आजीविका मिशन एवं कौशल विकास तथा स्वयं सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी बदल रही है। आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक बदलाव में भूमिका को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आम जनता के प्रति समर्पित एवं पूरी तरह से संवेदनशील है। जनधन योजना, उज्ज्वला, सौभाग्य एवं प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं में लाभार्थी खाते में धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है, जिससे पूरी की पूरी धनराशि लाभार्थी को प्राप्त हो रही है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त हो गई है और महिलाओं के जीवन में परिवर्तन का दौर शुरु हो चुका है। अब वह दिन दूर नहीं जब देश तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगा। ■

15 जुलाई से शुरू होगा दस्तक–2 अभियान

जे.ई./ए.ई.एस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु 'दस्तक' अभियान के अन्तर्गत प्रभावित 38 जनपदों में आयोजित किये गये पखवाड़ा कार्यक्रम की सफलता को देखते हुये 15 जुलाई, 2018 से दस्तक–2 कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। दस्तक–2 कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। जे.ई./ए.ई.एस. बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जनपदों में चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में यूनिसेफ एवं डब्ल्यू.एच.ओ. का सहयोग लिया जायेगा। समस्त निर्माणाधीन मिनी पी.आई.सी.यू. सेन्टर का निर्माण कार्य 31 मई तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

यूपी में बनेंगे 54 इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी मार्ग

मुख्यमंत्री जी का सपना है कि प्रदेश की सड़कों के मामले में एक विशिष्ट पहचान बने। दूसरे राज्य से जब कोई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करें तो उसे उत्तर प्रदेश की गुणवत्ता युक्त सड़कें महसूस होनी चाहिए।

धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त

गुणवत्तापूर्ण सड़को के निर्माण की ओर गंभरता से कार्य करते हुए सरकार ने चिन्हित 54 इन्टर स्टेट कनैक्टीविटी मार्गो के निर्माण हेतु सहमति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त कर दी है।

667.04 किलोमीटर होगी कुल लंबाई

प्रदेश में अन्तर राज्य कनैक्टीविटी के 54 मार्ग चिन्हित किये गये हैं, जिसकी कुल लम्बाई 667.04 किलोमीटर है तथा इनके निर्माण में कुल लागत रुपये 133252.82 लाख रुपये आयेगी।

शीघ्र प्रारंभ होगा निर्माण

जनपद आगरा के 10 मार्ग, गोरखपुर के 15 मार्ग, झांसी के 14 मार्ग, वाराणसी के 7 मार्ग, मुरादाबाद और मेरठ के दो–दो मार्ग तथा आजमगढ़ लखनऊ बरेली तथा फैजाबाद के एक–एक मार्ग इस प्रकार प्रदेश में कुल 54 मार्गो की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। शीघ्र ही इन मार्गो पर पूर्ण गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का होगा कार्य

इन सभी इन्टर स्टेट कनैक्टीविटी के 54 मार्गो में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराया जायेगा। सरकार यूपी को सड़को का स्वर्ग बनाने के लिए प्रयासरत है। ■

लखनऊ में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदूषण की समस्या से चिंतित हैं और इसके निराकरण हतु नित प्रयासरत हैं। लखनऊ शहर में प्रदूषण कम करने की दिशा में सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। लखनऊ शहर हेतु 40 इलेक्ट्रिक बसों के क्रय एवं चार्जिंग सिस्टम की स्थापना (Design, Manufacture, Supply and Commissioning of Midi Electric Buses along with Provisioning and Installation of Charging Infrastructure) हेतु मे0 टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षर किया गया।

इन बसों का ध्वनि एवं वायु प्रदूषण न्यूनतम होगा तथा शहर की जनता को आरामदायक सस्ती सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

शीघ्र ही अन्य शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन बसों के अतिरिक्त प्रथम चरण में लखनऊ एवं इलाहाबाद महानगरों में ग्रास कॉस्ट कान्ट्रेक्ट मॉडल पर नगरीय परिवहन की बसों का संचालन कराया जायेगा, जिससे शहरवासियों को अच्छी परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

लखनऊ में बनेगा देश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेटर

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यूपी को विश्व पटल पर एक नए स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार, व्यवसायिक तरलता के साथ नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई स्टार्टअप नीति के साथ बिलकुल तैयार है।

वित्त वर्ष 2018-19 में स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा 250.00 करोड़ की धनराशि बजट में आवंटित

नये स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और पूर्व संचालित स्टार्टअप की सहायता हेतु प्रदेश सरकार लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर स्थापित करने जा रही है। जिसके लिए नादरगंज अमौसी में 40 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गयी है।

आयोजित होंगी स्टार्टअप कार्यशालाएं

प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के सभी 18 डिवीजनों में स्टार्टअप कार्यशालाएं भी आयोजित करेगी। नए स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन के लिए 100 सलाहकारों का एक पैनल भी बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा भत्ते का भी प्रावधान रखा गया है।

सरकार यूपी में स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है और स्टार्टअप को सफल बनाने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है।

बिजनेस बढ़ाने पर विशेष ध्यान

अच्छे बिजनेस आइडिया को न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विकसित किया जा सकता है। सरकार स्टार्टअप बिजनेस को बढ़ाने और धन जुटाने के सुझावों पर गौर करते हुए बाजार में अग्रणी स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है।

कारीगरों और किसानों को लाभ

अवध क्षेत्र में कौन से व्यवसाय किये जा सकते हैं, पहले उनकी पहचान की जा रही है और फिर नई स्टार्टअप नीति से कारीगरों और किसानों को कैसे फायदा हो सकता है, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी व्यवसाय को विकसित करने के लिए स्टार्टअप नेटवर्क बनाना आवश्यक है, इसलिए सरकार मजबूत नेटवर्क बनाने की तैयारियां कर रही है।

सरकार ने स्टार्टअप पोर्टल http://itpolicyup.gov.in और स्टार्टअप हेल्पलाइन 0522-2286808, 2286809, 2286812, 4120202 शुरू किया है।

1000 करोड़ का कार्पस फण्ड स्टार्टअप के लिए

आईटी एवं स्टार्ट-अप नीति के तहत अब तक 10 इन्क्यूबेटर्स तथा 138 स्टार्ट-अप स्थापित

उत्तर प्रदेश में नवप्रवर्तन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा युवाओं को 'रोजगार आकांक्षी' के बजाय 'रोजगार प्रदाता' बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं। केवल उत्तर प्रदेश के स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1000 करोड़ रुपये से उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप फण्ड (कार्पस फण्ड) की स्थापना की जा रही है।

ईज आफ डूइंग बिजनेस सुधारों के जरिए व्यवसाय मित्रवत वातावरण का सृजन करने के लिए उद्योग बन्धु में सिंगिल विन्डो सिस्टम की स्थापना की गयी है। इसके अलावा निवेशकों, उद्यमियों तथा स्टार्ट-अप को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन में एक नीति क्रियान्वयन इकाई स्थापित की गयी है।

स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमियों तथा नव प्रवर्तकों के लिए आई.आई.टी. कानपुर, आई.आई.टी.-बीएच.यू., आई.आई.एम. लखनऊ तथा कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर जैसे अग्रणी संस्थानों आदि में 10 इन्क्यूबेटर्स विकसित किए गये हैं। इसमें 138 स्टार्ट-अप की स्थापना की जा चुकी है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी